सौर ऊर्जा क्षेत्र में सस्ते कर्ज पर नई नीति बनेगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सरकार नई नीति बना रही है। 'हिंदुस्तान' को मिली जानकारी के मुताबिक, इससे जुड़े कारोबारियों को उत्पादन के लिए सस्ता कर्ज देने की नीति पर वित्त मंत्रालय काम कर रहा है और इस बारे में दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जा सकते हैं।

इस मामले से जुड़े अधिकारी का कहना है कि मौजूदा समय में सोलर मॉड्यूल के उत्पादकों के लिए आसान और सस्ती दरों पर कर्ज मिलना चुनौती बना हुआ है। सरकार की कोशिश है कि इस मुश्किल से कारोबारियों को निजात दिलाई जाए और उत्पादन को प्रभावी बनाया जाए। ताकि देश में सौर ऊर्जा का हिस्सा बढ़ सके। इसके लिए सरकारी बैंकों को वित्त मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही इस क्षेत्र को प्राथमिक कर्ज वाले क्षत्रों में शामिल किया जा सकता है। ऐसा होने पर सरकारी बैंकों से आसानी से कम दरों पर उत्पादकों को कर्ज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आकलन में मौजूदा समय में इस सेक्टर को मिलने वाले कुल कर्ज का 60% से ज्यादा हिस्सा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों यानि एनबीएफसी के जरिये ही दिया जाता है।

आसान दरों पर कर्ज की पेशकश

पिछले कुछ दिनों में निजी क्षेत्र के बैंकों ने छोटे और मझोले कारोबारियों को सौर उर्जा का प्लांट लगाने के लिए आसान दरों पर कर्ज की पेशकश की है। इसके लिए बैंकों की तरफ से सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों की तरफ से रणनीतिक साझेदारी की गई है।